आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
वर्ष 1, अंक 1, जून 2015, पृ. 32–35

वैश्वीकरण की नीतियों का गोड़ एवं बैगा जनजाति की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव

प्रियांक जोशी *

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सम्पूर्ण विश्व के समाजों को वैधानिक प्राविधानों (विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संयुक्त आर्थिक संधि) द्वारा एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रुप में अंतर्सम्बन्धित करती है। इस प्रक्रिया का प्रभाव समाज के प्रत्येक आयाम (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रातनीतिक इत्यादि) पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप में दिखाई देता है। विगत 20–25 वर्शों से आर्थिक सुधार एवं आर्थिक उदारवादी वैचारिकी ने विश्व में निहित सम्पूर्ण देशों के मध्य एक नवीन अंतःक्रिया प्रणाली की संरचना अस्तित्व में आयी है, जिससे जनजातीय समुदाय भी अछूता नहीं हैं। सन् 1991 से भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्रों में सुधार प्रारम्भ किये गये हैं। वर्श 1991 के बाद वैश्वीकरण कि नीतियों का प्रभाव भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, कार्यक्रमों पर भी पड़ा है, जिसे भारत में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश में परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। उदारवाद एवं निजीकरण की नीतियो के लागू होने से सामाजिक क्षेत्रों– स्वास्थ, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं यातायात में मुख्यतः निरंतर सब्सीडी या सरकारी अनुदान कम किया गया है। यह आर्थिक सुधार एवं नियोजित समायोजन कार्यक्रम (सेप) का प्रमुख हिस्सा है, जो विश्व बैंक एवं अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोश द्वारा निर्देशित है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य मुद्दा मण्डला जिले की गोड़ एवं बैगा जनजातियों के शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकरण (नीतियों) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन क्षेत्र

मध्यप्रदेश भारत का जनजातीय बहुल राज्य है। वर्श 2011 भारत में जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है, जिनमें 77,19,404 पुरूष एवं 75,97,380 महिलायें है। मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14 प्रतिशत एवं मध्यप्रदश की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में गोड़ एवं बैगा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के रूप में मण्डला जिला को अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित किया गया।

मण्डला जिले में वर्श 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 4,54,932 गौड जनजाति के एवं 34,930 बैगा जनजाति में लोग निवास करते है जो की पूरे मध्य भारत में गौड़ एवं बैगा जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मण्डला जिले की कुल जनसंख्या 10,54,905 है जिसमें 6,10,528 जनजातीय जनसंख्या है, जोकि मण्डला की कुल आबादी का 58 प्रतिशत है ।

मण्डला जिला 4 तहसीलों क्रमशः नैनपुर, मण्डला, बिछिया एवं निवास में बंटा हुआ है। अध्ययन हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन द्वारा निवास तहसील के 4 गांव का चयन किया गया। वर्श 2001 कि जनगणना के अनुसार निवास तहसील में कुल 41,556 परिवार हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1,96,055 है जिनमें 98223 पुरूष एवं 97823 महिलायें हैं। इस प्रकार कुल 405 बैगा एवं गोड़ परिवारों के मुखिया से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्यों को एकत्र किया गया है। गोंड़ एवं बैगा उत्तरदाताओं द्वारा अपने बच्चों के लिये चयनित स्कूल के विषय में अभिमत दिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कुल 395 उत्तरदाताओं में से 390(98.7%) उत्तरदाताओं के बालक–बालिकाएं सरकारी स्कुल में पढ़तें है

***क्षेत्रीय समन्वयक, डब्ल्यू. टी. आर. ओ. मध्य प्रदेश**

जबकि मात्र 5(1.3%) उत्तरदाताओं के बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे है। तुलनात्मक रूप से 205(98.1%) बैगा एवं 185(99.5%) गोंड़ उत्तरदाताओं के बच्चे सरकारी स्कुलों में पढ़ते है जबकि 4(1.9%) बैगा एवं 1(0.5%) गौंड़ उत्तरदाताओं के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते है। इससे स्पष्ट है कि दोनों ही जनजातियों के उत्तरदाताओं में से अधिकतम उत्तरदाताओं के बच्चे या परिवार के बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़तें है। अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि चयनित किये गये चारों गॉवों (परतला, बम्हनी, डोभी एवं डोभा) में कोई भी निजी विद्यालय नहीं है।

बालक एवं बालिकाओं को सरकारी स्कूलों में पढ़ायें जाने के विशय में अभिमत पूछे गये, जिससे स्पष्ट हुआ कि संयुक्त रूप से कुल 9(2.3%) गोड़ एवं बैगा उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो रही है तथा इसके समान ही 9(2.3%) उत्तरदाताओं मानते हैं कि गाँव के आसपास कोई अच्छा निजी विद्यालय नहीं है इसलिये वे मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते है, साथ ही 298(73.4%) मानते हैं कि गाँव के आस–पास उपलब्ध निजी विद्यालयों की फीस बहुत ज्यादा है एवं उनकी सीमा के बाहर है अन्यथा वे अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते तो 87(22.0%) लोगों ने दूसरे एवं तीसरे अर्थात् दोनों विकल्पों के चुना अर्थात् गाँव के आस–पास स्कूल नहीं है लेकिन जो हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है।

तुलनात्मक रूप से किसी भी बैगा उत्तरदाता ने यह स्वीकार नहीं किया की सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती हैं, जबकि 9(4.8%) गोंड़ उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि 5(2.4%) बैगा एवं 4(2.2%) गौंड़ उत्तरदाताओं के अनुसार गॉव के आसपास कोई भी निजी स्कूल नहीं है जबकि 154(73.4%) बैगा एवं 136(73.4%) गौंड़ उत्तदाताओं के अनुसार निजी स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है की ये लोग अपने बच्चों को चाह कर भी नहीं पढ़ा सकते है, वहीं 50(23.9%) बैगा एवं 37(19.9%) गौंड़ उत्तरदाताओं के अनुसार आस–पास स्कूल नहीं है जो स्कूल है, उनकी फीस बहुत ज्यादा है।

बैगा एवं गोड़ उत्तरदाताओं द्वारा सरकारी स्कूलों के चयन के विषय में प्राप्त अभिमतों का बिन्दु रेखीय प्रदर्शन(1.1)

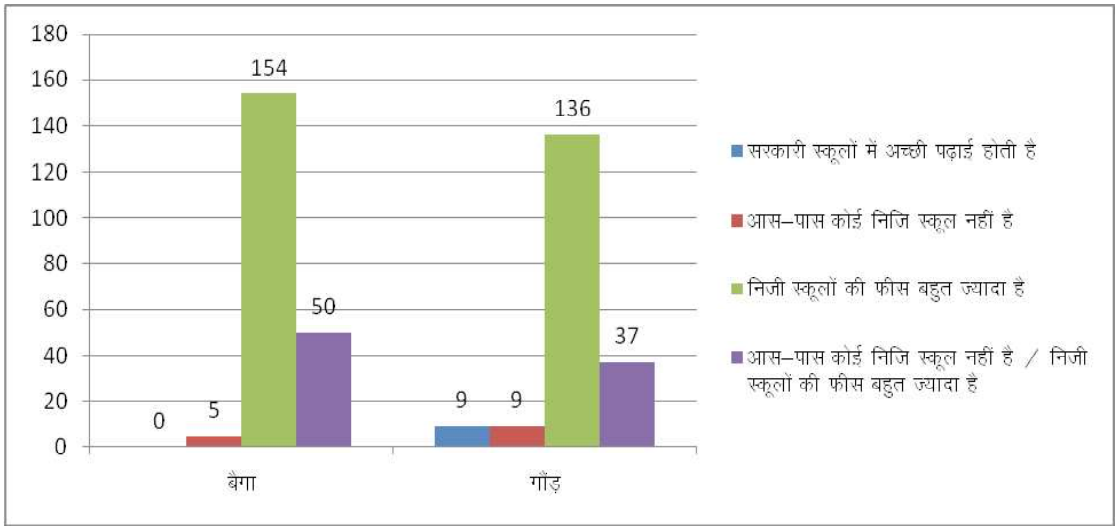

उपरोक्त अभिमतों का प्रमाणीकरण अवलोकन के द्वारा भी किया गया तथा दोनों ही समुदाय के लोगों ने यह बताया कि वे मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे है क्योंकि गाँव के आस–पास उपलब्ध निजी स्कूलों में वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते है क्योंकि उनकी मासिक आय बच्चों के मासिक खर्चे से भी कम है ।

सयुंक्त रूप से कुल बैगा एवं गोड़ उत्तरदाताओं में से मात्र 9(2.3%) उत्तरदाताओं ने सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई के प्रति संतुष्टी प्रकट की है, जबकि 386(97.7%) उत्तरदाताओं ने बताया की वे सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई से संतुश्ट नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पश्ट है की दोनों ही समुदाय के उत्तरदाता अपने बच्चों की सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण के सम्बन्ध में 9(2.3%) उत्तरदाताओं ने सरकारी विद्यालयों में अपर्याप्त शिक्षक, 27(6.8%) ने सरकारी विद्यालयों में आवश्यक अधोसरंचना का अभाव, 49(12.4%) ने सरकारी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है, बताया अर्थात सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है जबकि अधिकतम 395(100%) उत्तरदाताओं ने यह बताया की उपरोक्त सभी कारणों से वे सरकारी स्कूलों से संतुश्ट नहीं है ।

तुलनात्मक रूप से 7(3.3%) बैगा एवं 2(1.1%) गौंड़ उत्तरदाताओं ने अपने असंतोश का कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, 16(7.7%) बैगा एवं 11(5.9%) गौंड़ उत्तरदाताओं ने सरकारी अधोसंरचना की कमी, 23(11.0%) बैगा एवं 26(14.0%) गौंड़ उत्तरदाताओं ने बताया की सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर गुणवत्ता वाला नहीं है। 1(0.5%) बैगा उत्तरदाता के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों का सम्पूर्ण विकास नहीं होता है जबकि 162(77.5%) बैगा एवं 147(79.0%) गोड़ उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सभी कारणों की वजह से सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा के प्रति असंतुश्टी दर्ज की है ।

बैगा एवं गोंड़ जनजातिओं के उत्तरदाताओं का सरकारी विद्यालयों की शिक्षा के विषय में अभिमतों का बिन्दु रेखीय प्रदर्शन (1.2 ब)

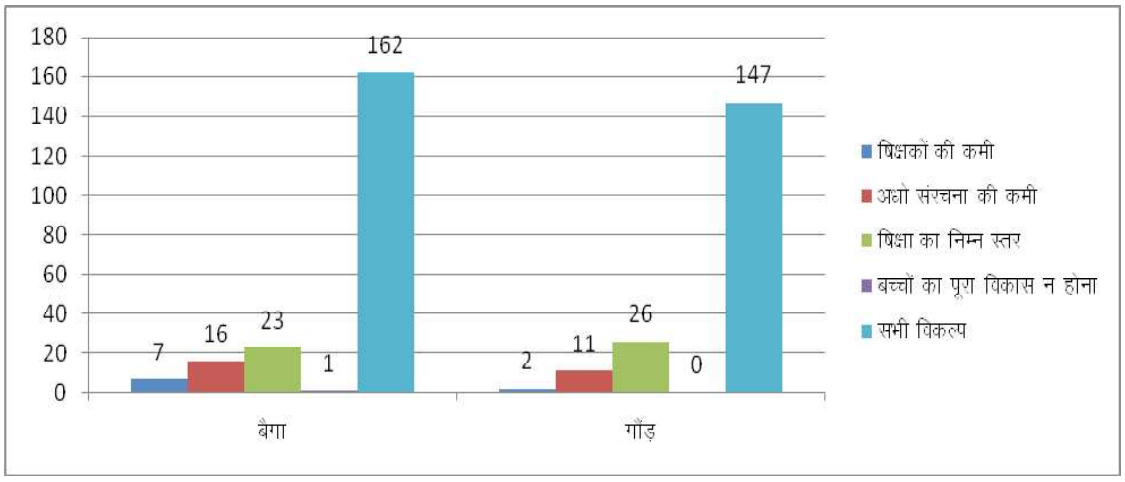

उपरोक्त अभिमतों एवं तथ्यों से यह स्पष्ट होता है की दोनों ही प्रकार के जनजातीय उत्तरदाता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते है। संसाधनों की कमी की वजह से वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं भेज पा रहे हैं ।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण की नीतियों के लागू होने के उपरान्त (सन् 1991 के पश्चात) भारत सरकार ने नियोजित समायोजन कार्यक्रम (सेप) के तहत सामाजिक क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता या अनुदान या सब्सीडी लगातार कम की है जिसमें शिक्षा का क्षेत्र भी षामिल है ।

यदि हम विभिन्न पचंवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के मद पर आवंटित राशि को देखें तो हम देख सकते है की पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) में शिक्षा पर किये गये खर्च का प्रतिशत कुल बजट का 7.86% था जो कि ऑठवी पचंवर्शीय योजना (1992–97) में 4.50% तक कम हुआ जबकि भारत कि जनसंख्या में इन 40 वर्शो में कई गुना वषद्धि हुई है परन्तु शिक्षा पर खर्च कि जाने वाली राशि कम हुई है वैश्वीकरण कि इस नीति का क्रियान्वयन शोध क्षेत्र के चारों गाँवों में भी देखा जा सकता है ।

वर्ष 1995 मे इन चारों गाँवों में कुल मिलाकर 5 प्राथमिक एवं 2 माध्यमिक स्कूल थे जबकि शिक्षकों की कुल संख्या 10 थी वर्ष 2011 में भी इन चारों गाँवों में 5 प्राथमिक एवं 2 माध्यमिक स्कूल है एवं शिक्षकों की संख्या 10 ही है अर्थात विगत 15 से 16 वर्षो में बच्चों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है। अधोसंरचना के विषय में भी चारों गाँवों के विद्यालयों में कई सारी सुविधायें नहीं है। यदि शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाये तो प्राथमिक स्कूल में पढ़नें वाले बच्चें अच्छे से लिख–पढ़ नहीं पाते हैं ।

दोनों ही जनजातियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण जनजातीय बालक–बालिकाएं नौकरी के लिये आवश्यक योग्यता हासिल नहीं कर पाते है। जनजातीय के लिए आरक्षण उपलब्ध होने के बाद भी गाँव के इक्का–दुक्का लोग ही सरकारी या गैर–सरकारी नौकरी प्राप्त कर पायें है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण कि नीतियों से पिछले 20 वर्षो में इन गॉवों में शिक्षा, शिक्षक एवं स्कूलों कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। जनजातीय जनसंख्या धनाभाव एवं ससांधनों की कमी के कारण अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। नियोजित समायोजन कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान के कम होने से जनजातीय बालक–बालिकाओं की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है ।

मध्यप्रदेश की शिक्षा दर वर्श 2011 की जनगणना के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार 70.6 प्रतिशत है जबकि इसी जनगणना के अनुसार मण्डला जो की जनजाति बहुल जिला है की शिक्षा दर 68.3 प्रतिशत है। वर्तमान नीतियॉ इस दर को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सहायक नहीं है वरन् मात्र गुणवत्ता–विहीन शिक्षा के फैलाव में सहायक है। उपरोक्त विवेचन से स्पश्ट है कि वर्तमान नीतियॉ जो कि वैश्वीकरण की नीतियों का अनुसरण करके बताई गई है जो गरीब एवं पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों एवं लोगों के लिये नकारात्मक है। विगत 15 से 20 वर्षो में सरकारी स्कूलों एवं शिक्षकों कि संख्या में वृद्धि नहीं हुई है इसके विपरीत गाँव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर निजी स्कूल उपलब्ध हुये है, जो कि सर्वसाधन सम्पन्न है परन्तु जनजाति के लोगों की उन तक पहुॅच नहीं है क्योंकि इन स्कूलों की फीस उनकी आय से कई गुना ज्यादा है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अर्थेइल, मैथ्यु 2009 : ''इम्पैक्ट आफ ग्लाबलाइजेशन आन ट्राइब्स, रावत पब्लिकेशन।

अरोरा, रास्मे 2003 : हाउ ग्लोबलाइजेशन एफेक्टस इंडिया चिल्डरन्स, बुक एण्ड रिपोर्ट शेयर कमेंट।

चंतिया, आलोक 2009 : दी इम्पेक्ट आफ ग्लाबलाइजेशन आन ट्राइब्स, रिसर्च पेपर: www.alok chantiyabalogspot.com

सागर, वी.के. 2005 : ग्लोबलाइजेशनः काउंटर करेंट. ओ.आर.जी.

श्याम, लाल 1987 : दी एजुकेशन एमांग ट्राइबल, जयपुर, प्रिंटेल पब्लिशर्स।

सिंह, विनोद 2003 : दी इम्पेक्ट आफ नान फारमल एडुकेशन आन गोंड एण्ड बैगा ट्राइब्स, अप्रकाशित शोध प्रबंध, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.।